प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
18.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

सम्मान निधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के साथ इस योजना के अंतर्गत देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को तीन लाख 70 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना में किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रूपए दिये जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन मानदंडों में उचित संशोधन का आग्रह किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृति और नुकसान को देखते हुए पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत परस्पर निर्भर और सतत विकास ढांचे का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए वन भूमि पर आवास निर्माण के लिए एक बीघा तक भूमि देने की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान करने की मांग भी की।

मनाली–लेह सड़क

प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली 4 सौ 35 किलोमीटर मनाली–लेह सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद कर दी जाएगी। सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी ने भारी बर्फबारी की आशंका और सड़क पर ब्लैक जैसी परिस्थितियों को देखते हुए लाहौल स्पीति व कुल्लू जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। लाहौल स्पीति जिला उपायुक्त ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस सड़क को अगले वर्ष मई–जनू में बर्फ हटाने के बाद ही दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा।

भूमि लीज

राज्य सरकार ने सरकारी भूमि को लीज पर देने की अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष कर दी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बिजली परियोजनाओं, पर्यटन, उद्योग व अन्य परियोजनाओं को भूमि 40 वर्ष के लिए लीज पर मिलेगी। हालांकि हिमुडा में रियायत देते हुए सरकार ने लीज की अवधि 80 वर्ष निर्धारित की है।

दैनिक भत्ता

मंत्रियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते में प्रदेश सरकार ने बढ़ौतरी की है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब मंत्रियों के दैनिक भत्ते को 18 सौ से बढ़ाकर 25 सौ रूपए कर दिया गया है। विधायकों के दैनिक भत्ते में सरकार पहले ही बढ़ौतरी कर चुकी है।

बिक्रम ठाकुर

पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में मनाए जाने वाले जश्न समारोह का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है।

मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कांग्रेस की सरकार पिछले तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आज ये कहा जा रहा है कि तीन वर्ष का जश्न शीघ्र मनाया जाएगा और ये जश्न किस बात का। पूरा हिमाचल प्रदेश दुखी है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। महिलाओं को गारंटियों के माध्यम से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है। नौजबानों को बोला गया कि एक वर्ष के अंदर एक लाख नौकरियां देंगे। वे उन नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। बागवान किसान दुखी हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। कर्मचारी हर रोज आवाज उठाते हैं कि उनके हक नहीं मिल रहे। पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, तो जश्न किस बात का।

राष्ट्रीय राजमार्ग 70

मंडी जिले में निर्माणाधीन हमीरपुर से मंडी वाया धर्मपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 70 की प्रगति और प्रभावित लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर मंडी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क निर्माण के दौरान घरों को हुए नुकसान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता....

बैठक में विधायक अनिल शर्मा, चन्द्रशेखर, दिलीप ठाकुर तथा उपायुक्त अपूर्व देवगन उपस्थित रहे, जबकि शिमला से आरओ मोर्थ ए.के.कुशवाहा ने वर्चुअली भाग लिया। बैठक में सड़क की गुणवत्ता, कटिंग से प्रभावित घरों की सुरक्षा तथा निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायकों की मांग पर 23, 24 और 25 नवम्बर को तीन चरणों में संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। 23 नवम्बर को मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत तल्याहड़ से सीहण तक, 24 नवम्बर को अवाहदेवी से पाड़छु तक और 25 नवम्बर को पाड़छु से सीहण तक निरीक्षण टीम सभी संवेदनशील स्थानों का जायजा लेगी। निरीक्षण में संबंधित विधायक, राजस्व, लोक निर्माण, जलशक्ति और बिजली बोर्ड के अधिकारी, मॉर्थ के अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

विधायकों ने बैठक में सड़क निर्आमाण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू के बाहर हुए घरों को नुकसान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस पर आरओ शिमला ने बताया कि कटिंग से घरों की सुरक्षा के लिए कंक्रीट ढंगे लगाने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जा चुका है।